



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी-विंग', 59, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./ 102 /NREGS-MP/स्था./NR-1/09

भोपाल, दिनांक 8/1/2009

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला (समस्त 50 जिले)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला पंचायत, जिला (समस्त 48 जिले)
मध्यप्रदेश।

विषय : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. अंतर्गत समस्त कार्यों को नागरिक सूचना पटल पर प्रदर्शन किये जाने विषयक।

संदर्भ : संयुक्त सचिव, (NREGA) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र क्र. M-11011/5/2007-NREGA-II दिनांक 15 अक्टूबर, 2009

संदर्भित पत्र द्वारा अवगत किया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. के अंतर्गत क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर सूचना पटल नहीं लगाये जा रहे हैं। आपको यह ज्ञात होगा कि योजना में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिये सूचना पटल का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान होता है।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में प्रत्येक कार्य स्थल पर सूचना पटल (लोहे के बोर्ड अथवा सीमेंट प्लास्टर किया हुआ) अनिवार्यतः लगाया जावे। सूचना पटल में जिन बिंदुओं का समावेश किया जाना है, उसका प्रारूप संलग्न है।

Ashtini
6/1/09
(रश्मि अरूण शर्मा)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

भोपाल, दिनांक 8/1/2009

पृ.क्र./ 103 /NREGS-MP/स्था./NR-1/09

प्रतिलिपि

समस्त संभाग आयुक्त, की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Ashtini
6/1/09
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्-म.प्र.



नागरिक सूचना बोर्ड

ग्राम पंचायत का नाम..... जनपद पंचायत का नाम

जिला

1. कार्य/परियोजना का नाम :
2. a) योजना नं.एवं कोड (परियोजना ID) :
b) उपयोग में लाये गए मास्टर रोल्लस का क्रमांक :
3. परियोजना का संक्षिप्त विवरण :
4. घटक :
(i) परियोजना की प्राक्कलित लागत (ii) वास्तविक व्यय
- a) मजदूरी अंश :
b) सामग्री अंश :
5. परियोजना के अंतर्गत सृजित मानव दिवस की संख्या एवं प्राक्कलन।
a) प्राक्कलन :
b) वास्तविक :
c) व्यक्तियों की संख्या जिन्हें रोजगार पर नियोजित किया गया।
6. महत्वपूर्ण दिनांक :
a) कार्य की स्वीकृति :
b) परियोजना प्रारंभ :
c) पूर्ण कार्य :

P.T.O.

7. क्रियान्वयन संस्था :

a) नाम :

b) पता :

c) दूरभाष नं. :

8. सरकारी तकनीकी एवं प्रशासनिक अमला जो निरीक्षण हेतु उत्तरदायी है

a) नाम :

b) पदनाम :

c) पता :

d) दूरभाष नं. :

9. नाम और पता :

a) अध्यक्ष :

सतर्कता एवं निगरानी समिति

b) सदस्य :

सतर्कता एवं निगरानी समिति :

3/c

No. M-12014/8/2006-NREGA (Part)
Government of India
Ministry of Rural Development
(Mahatma Gandhi NREGA Division)

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated the 4th March, 2010

To

The Principal Secretary/Secretary
(Rural Development)
All States/UTs

Dear Sir/Madam,

With a view to infusing transparency and enhancing the integrity of wage payment under Mahatma Gandhi NREGA, and also to encourage savings among the rural poor, Schedule II of Mahatma Gandhi NREGA Act has been amended to make wage disbursement to Mahatma Gandhi NREGA workers through institutional accounts in Banks or Post Offices a statutory requirement. Accordingly, as of now 8.60 crore Mahatma Gandhi NREGA workers accounts have been opened in the Banks and Post Offices. About 82% of wages i.e. nearly about Rs. 16959.14 crores of wages have been disbursed through these accounts up to December, 2009 constituting 70 per cent of the total expenditure under Mahatma Gandhi NREGA.

2. The pace of financial inclusion under Mahatma Gandhi NREGA has surpassed the pace of institutional outreach of Banks and Post Offices as well as their current capacity to manage such a large number of accounts. This has led to delay in wage disbursements which legally entails payment of compensation. It is imperative therefore that the twin legal mandates of wage payments within the stipulated 15 days as well as of wage disbursement through institutional accounts be scrupulously adhered to.

3. To strengthen the institutional outreach for Mahatma Gandhi NREGA wage disbursement the option of the Business Correspondence model has been under discussion for some time. While this model holds potential for reaching out to Mahatma Gandhi NREGA workers in yet un-reached areas, the service charge of 2% sought by the Banks for appointing business correspondents has discouraged State Governments from using the model.

4. As a result of several discussions, it has emerged if a Bank takes the initiative, it would be possible for it to absorb the business correspondent service costs within the float available from the volume of funds placed with it.

5. Accordingly, States may identify unserved areas where the BC model may be required and discuss with banks the possibility of extending the BC model in these areas. The possibility of using Self Help Groups in this may also be examined.

18/3/10
18/3/10
18/3/10
18/3/10
18/3/10

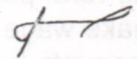
(e/d)
on file
urgent
प्रतिपत्र पत्र

360
19/3/10

6. To ensure that there are no backlogs in wage disbursements the DPCs will ensure that the Gram Rozgar Diwas will be held compulsorily every month on a pre-announced date at the Gram Panchayat level in which all the Mahatma Gandhi NREGA workers will be called and all issues pertaining to wage payments will be resolved. For this purpose, the District Programme Coordinator will deploy the administrative resource available in the district like the Revenue personnel for monitoring timely payments. This system of monthly verification for the wage payment will be compulsory implemented through out the State.

7. Any delay in wage payments by any agencies/ persons or any unfair means in wage payment which deprives the workers of their due wage amount will be punishable under Section 25 of the Act. The District Programme Coordinator will be responsible for invoking this section to ensure that the DPC/s function under Section 14 (2) of the Act is properly discharged. Appropriate compensation will be payable to NREGA workers in case wages are paid beyond 15 days of work done. The institutional agency responsible for delay in wage payment to administrative machinery or the financial institution whichever the case may be, will be responsible for paying the compensation.

Yours sincerely,



(AMITA SHARMA)
Joint Secretary

3. To strengthen the institutional outreach for Mahatma Gandhi NREGA wage disbursement, the option of the Business Correspondence model has been under discussion for some time. While this model holds potential for reaching out to Mahatma Gandhi NREGA workers in far unstaffed areas, the service charge of 2% sought by the banks for appointing business correspondents has discouraged State Government from using the model.

4. As a result of several discussions, it has emerged that a Bank takes the initiative, it would be possible for it to assess the business correspondent service costs within the local available fund the volume of funds placed with it.

5. Accordingly, States may identify approved areas where the BC model may be required and discuss with banks the possibility of extending the BC model in these areas. The possibility of using Self Help Groups may also be examined.

Handwritten notes and stamps on the right side of the page, including a date stamp '2011' and other illegible markings.



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी-विंग', 59, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./ 15303/NR- /09 भोपाल,

दिनांक 18/12/2009

प्रति,

1. कमिश्नर,(समस्त)
2. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक, समस्त जिले
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
समस्त जिले
मध्यप्रदेश
4. संचालक, एसआईआरडी, जबलपुर

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी दर में संशोधन विषयक।

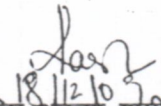
संदर्भ: भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. Z-11011/1/09

दिनांक 03.12.09

1. वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी दर रूपये 91/- निर्धारित है। यह मजदूरी दर दिनांक 01.01.09 से भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अनुसार स्वीकृत है।
2. संदर्भित पत्र एवं भारत शासन की अधिसूचना दिनांक 15.12.09 के अनुसार भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी दर राशि रू. 100/ प्रतिदिवस स्वीकृत की है। यह मजदूरी दर 01.10.09 से प्रभावशील होगी। अतः तदनुसार मजदूरी राशि के भुगतान करें।

यह भी अवगत कराया जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. के अंतर्गत भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्धारण अनुसार न्यूनतम मजदूरी दर देय होगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार


(रशि अरुण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
भोपाल



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2121]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 2009/अग्रहायण 24, 1931

No. 2121]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2009/AGRAHAYANA 24, 1931

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2009

का.आ. 3208(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक का.आ. 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

- (i) क्रम संख्यांक 1 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "100.00 रु. (2 दिसम्बर, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (ii) क्रम संख्यांक 2 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "100.00 रु. (21 मई, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (iii) क्रम संख्यांक 3 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "80.00 रु. (1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (iv) क्रम संख्यांक 4 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "100.00 रु. (1 जून, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (v) क्रम संख्यांक 8 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "100.00 रु. (10 अगस्त, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;

- (vi) क्रम संख्यांक 9 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "100.00 रु. (1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (vii) क्रम संख्यांक 11 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "100.00 रु. (1 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (viii) क्रम संख्यांक 14 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "100.00 रु. (24 अगस्त, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (ix) क्रम संख्यांक 18 (क) के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "100.00 रु. (14 मई, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (x) क्रम संख्यांक 18 (ख) के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "100.00 रु. (14 मई, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (xi) क्रम संख्यांक 18 (ग) के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "100.00 रु. (14 मई, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (xii) क्रम संख्यांक 21 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "100.00 रु. (1 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (xiii) क्रम संख्यांक 22 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "100.00 रु. (1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (xiv) क्रम संख्यांक 24 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "87.50 रु. (2 दिसम्बर, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;

- (xv) क्रम संख्यांक 25 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "83.73 रु. (1 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (xvi) क्रम संख्यांक 26 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "99.00 रु. (2 जून, 2009 से प्रभावी)" प्रविष्टि रखी जाएगी;

[फा. सं. जे.-11013/2/2008-एनआरडीजेए]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 1 जनवरी, 2009 में संख्यांक का.आ. 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2876(अ), तारीख 11 नवम्बर, 2009 द्वारा उसका अंतिम संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th December, 2009

S.O. 3208(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 1(E), dated the 1st January, 2009, nemely :—

In the said notification, in the Schedule,—

- (i) against Sl. No. 1, for the entry in column (3), the entry "Rs. 100.00 (with effect from 2nd December, 2009)" shall be substituted;
- (ii) against Sl. No. 2, for the entry in column (3), the entry "Rs. 100.00 (with effect from 21st May, 2009)" shall be substituted;
- (iii) against Sl. No. 3, for the entry in column (3), the entry "Rs. 80.00 (with effect from 1st April, 2009)" shall be substituted;
- (iv) against Sl. No. 4, for the entry in column (3), the entry "Rs. 100.00 (with effect from 1st June, 2009)" shall be substituted;
- (v) against Sl. No. 8, for the entry in column (3), the entry "Rs. 100.00 (with effect from 10th August, 2009)" shall be substituted;

- (vi) against Sl. No. 9, for the entry in column (3), the entry "Rs. 100.00 (with effect from 1st April, 2009)" shall be substituted;
- (vii) against Sl. No. 11, for the entry in column (3), the entry "Rs. 100.00 (with effect from 1st October, 2009)" shall be substituted;
- (viii) against Sl. No. 14, for the entry in column (3), the entry "Rs. 100.00 (with effect from 24th August, 2009)" shall be substituted;
- (ix) against Sl. No. 18 (a), for the entry in column (3), the entry "Rs. 100.00 (with effect from 14th May, 2009)" shall be substituted;
- (x) against Sl. No. 18 (b), for the entry in column (3), the entry "Rs. 100.00 (with effect from 14th May, 2009)" shall be substituted;
- (xi) against Sl. No. 18 (c), for the entry in column (3), the entry "Rs. 100.00 (with effect from 14th May, 2009)" shall be substituted;
- (xii) against Sl. No. 21, for the entry in column (3), the entry "Rs. 100.00 (with effect from 1st October, 2009)" shall be substituted;
- (xiii) against Sl. No. 22, for the entry in column (3), the entry "Rs. 100.00 (with effect from 1st April, 2009)" shall be substituted;
- (xiv) against Sl. No. 24, for the entry in column (3), the entry "Rs. 87.50 (with effect from 2nd December, 2009)" shall be substituted;
- (xv) against Sl. No. 25, for the entry in column (3), the entry "Rs. 83.73 (with effect from 1st October, 2009)" shall be substituted;
- (xvi) against Sl. No. 26, for the entry in column (3), the entry "Rs. 99.00 (with effect from 2nd June, 2009)" shall be substituted.

[F.No. J-11013/2/2008-NREGA]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st January, 2009 *vide* No. S.O. 1(E), dated the 1st January, 2009 and last amended *vide* notification number, S.O. 2876 (E) dated the 11th November, 2009.

No J-11011/1/2009-NREGA
Government of India
Ministry of Rural Development
(NREGA Division)

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated 3rd December, 2009.

To

The Principal Secretary/Secretary
Department of Rural Development
All States/UTs

Subject: Wage Rate Revision under section 6(1) of NREGA

Sir/Madam,

1. Your attention is drawn to Section 6(1) of NREGA:

"Notwithstanding anything contained in the Minimum Wages Act, 1948, the Central Government may, by notification, specify the wage rate for the purposes of this Act:

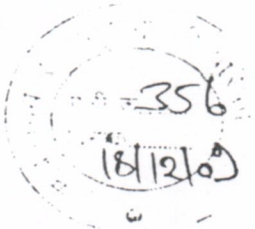
Provided that different rates of wages may be specified for different areas:

Provided further that the wage rate specified from time to time under any such notification shall not be at a rate less than sixty rupees per day."

2. The Central Government in exercise of power vested in it under Section 6(1) has decided upon the following policy for wage rate revision for the purposes of NREGA.

- 12/09
- 18/12/09
- i) Proposals received from State Government for wage revision under Section 6 (1) of NREGA may be considered and acceded to by the Central Government and notified subject to the ceiling of Rs.100/- per day. Anything higher than this would be paid by the State Governments from their own budgets.
 - ii) States with Wage Rates above Rs.100/- per day, as notified by the Central Government on 1st January, 2009, will be retained at that level.
 - iii) The new wage rates will be effective from 1st April, 2009 or from the date of actual disbursement whichever is later.

Contd..p/2..



- iv) States are advised that in future the new wage rates will be made effective only from the date of notification by the Government of India and not from retrospective date.
- v) In future, should a State Government seek to revise wage rates under NREGA the proposal for such a revision will have to be first submitted to Government of India and the revised wage rate as approved by Government of India will be applicable from the date indicated in the Government of India notification. State Governments will be liable for any difference in payment of wage rates caused by any deviation from this policy.

Yours sincerely,


(AMITA SHARMA)
Joint Secretary (NREGA)

S.No.	Name of State	Wage Rate in Rs. Per day	With Effect From
1	Assam	Rs. 100/-	2 nd December, 2009
2	Andhra Pradesh	Rs. 100/-	21 st May, 2009
3	Arunachal Pradesh	Rs. 80/-	1 st April, 2009
4	Bihar	Rs. 100/-	1 st June, 2009
8	Jammu & Kashmir	Rs. 100/-	10 th August, 2009
9	Karnataka	Rs. 100/-	1 st April, 2009
11	Madhya Pradesh	Rs. 100/-	1 st October, 2009
14	Meghalaya	Rs. 100/-	24 th August, 2009
18.	Punjab-		
(a)	Hoshiarpur	Rs. 100/-	14 th May, 2009
(b)	Jalandhar	Rs. 100/-	14 th May, 2009
(c)	Nawanshar	Rs. 100/-	14 th May, 2009
21.	Tamil Nadu	Rs. 100/-	1 st October, 2009
22	Tripura	Rs. 100/-	1 st April, 2009
24.	West Bengal	Rs. 87.50	2 nd December, 2009
25.	Chattisgarh	Rs. 83.73	1 st October, 2009
26.	Jharkhand	Rs. 99/-	2 nd June, 2009